

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. आपराधिक दूसरी विविध सजा के निलंबन की याचिका

(अपील) संख्या 2062/2023

में

एस.बी. आपराधिक अपील संख्या 1072/2022

हजारी लाल पुत्र दौलतराम, निवासी पीपळखेदडी मीना, तहसील छाबड़ा, जिला बारां
(वर्तमान में केंद्रीय कारागार झालावाड़ में बंद)

---याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, वी.एस. कुमार, निरीक्षक कार्यालय, नारकोटिक्स
कमिश्नर, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर, म.प्र. के माध्यम से, विशेष पी.पी.
झालावाड़ के माध्यम से

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री के.एन. शर्मा

प्रतिवादी की ओर से : श्री तेज प्रकाश शर्मा, विशेष पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन

आदेशरिपोर्ट करने योग्य11/03/2024

1. यह दूसरी सजा के निलंबन की याचिका लंबित अपील में दायर की गई है, जो
सत्र मामले संख्या 128/2015 में 01.06.2022 को विद्वान विशेष न्यायाधीश

(एनडीपीएस मामले), झालावाड़ द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई थी, जिसके तहत अपीलकर्ता-अभियुक्त हजारी लाल को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/19 और 8/26 के तहत दोषी ठहराया गया था और क्रमशः ₹1,00,000/- के जुर्माने के साथ 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹10,000/- के जुर्माने के साथ 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने एनडीपीएस नियम, 1985 के नियम 17 और 18 के अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन पर विचार किए बिना अपीलकर्ता-अभियुक्त को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/19 के तहत दोषी ठहराया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियम 18 में प्रावधान है कि सीलबंद अफीम को खोला जाना चाहिए और काश्तकार की उपस्थिति में नमूना लिया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान मामले में काश्तकार को कोई नोटिस नहीं दिया गया था और उसकी अनुपस्थिति में नमूना लिया गया था, इसलिए, नियम 18 का पालन न करने के कारण दोषसिद्धि को रद्द करने योग्य है। उन्होंने विशेष रूप से एस.बी. आपराधिक विविध सजा के निलंबन की याचिका संख्या 385/2022 में एस.बी. आपराधिक अपील संख्या 558/2022 में **रमेश बनाम यूनियन ऑफ इंडिया** नामक 27.01.2023 के आदेश पर भरोसा किया है, जिसमें एक समन्वय पीठ ने रमेश पुत्र धूनी लाल की सजा के निलंबन की याचिका को स्वीकार कर लिया है।

3. उपरोक्त तर्कों का विशेष लोक अभियोजक ने इस आधार पर विरोध किया कि यह अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा काश्तकारों के संदर्भ में गबन (embezzlement) और गैर-अनुपालन का मामला है, इसलिए वह किसी भी राहत का हकदार नहीं है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि नियम 18 सिर्फ एक निर्देशात्मक (directory) नियम है न कि एक अनिवार्य (mandatory) नियम, इसलिए अपीलकर्ता किसी भी तरह की राहत का हकदार नहीं है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि तौल के समय अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता मौके से भाग गया था और वह मौके पर मौजूद नहीं था, इसलिए उसकी उपस्थिति में नमूना नहीं लिया जा सकता था।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील और विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया।

5. 10.08.2023 को, इस न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ता के तर्क पर विचार किया था और पहली सजा के निलंबन की याचिका को खारिज कर दिया था। विद्वान वकील द्वारा उठाए गए आधार बिल्कुल समान थे और आदेश का कुछ हिस्सा निम्नानुसार पुनरुत्पादित है:

"वर्तमान अपीलकर्ता पर यह आरोप है कि वर्ष 2011-12 में 3500 वर्ग मीटर क्षेत्र में खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद अपीलकर्ता ने 3612 वर्ग मीटर में अफीम की खेती की और 6 किलोग्राम शुद्ध अफीम के बजाय 8.480 किलोग्राम (मिलावटी) अफीम जमा की गई और वही मिलावटी पाई गई, इसलिए, अपीलकर्ता पर नियम या उसके तहत दिए गए आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

विद्वान ट्रायल कोर्ट ने 14.10.2015 के अपने आदेश में आरोप के चरण में वर्तमान अपीलकर्ता के प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए, इस तथ्य पर विचार किया कि लम्बरदार की उपस्थिति में, जमा की गई अफीम को तोला गया और सील किया गया।

जहां तक अभियोजन के साक्ष्य का संबंध है, वर्तमान अपीलकर्ता को अफीम की खेती करने का लाइसेंस दिया गया था और इस तथ्य से ट्रायल के दौरान पीडब्ल्यू1 के साक्ष्य के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा इनकार नहीं किया गया था। 01.03.2012 से 23.03.2012 तक अपीलकर्ता द्वारा कुल 6 किलोग्राम अफीम जमा की गई थी और वही बाबूलाल द्वारा प्राप्त की गई थी और जिसे अच्छी पाया गया था। पीडब्ल्यू1 ने आगे कहा कि प्लास्टिक कंटेनर में अपीलकर्ता ने 2.440 किलोग्राम अफीम जमा की थी, जो मिलावटी पाई गई थी। जब उपरोक्त से नमूना लिया गया, तो वर्तमान अपीलकर्ता हजारी लाल केंद्र से भाग गया। उसके बाद, पीडब्ल्यू4 (लम्बरदार) बाबूलाल की उपस्थिति में, नमूना लिया गया और शेष कंटेनर को जब्त कर लिया गया। पीडब्ल्यू1 ने स्वीकार किया कि जब नमूना लिया गया था तब अपीलकर्ता-हजारी लाल मौके पर मौजूद नहीं था।

पीडब्ल्यू1 के बयान ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि नमूना सौंपने के बाद, हजारी लाल केंद्र से भाग गया। पीडब्ल्यू4 बाबूलाल ने आगे मुख्य गवाही में कहा कि 2.440 किलोग्राम अफीम मिलावटी पाए जाने के बाद। एक नमूना लिया गया और उसने इस तथ्य को साबित किया कि कंटेनर और नमूना उसकी उपस्थिति में जब्त किए गए थे। जिरह के दौरान यह खंडन करने के लिए कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछा गया था कि अफीम अपीलकर्ता की नहीं थी। पीडब्ल्यू5 बलवंत सिंह जैन वह व्यक्ति था जिसने इस अफीम की जाँच की थी और जब अपीलकर्ता की उपस्थिति के बारे में पूछा

गया तो उसने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता वहां नहीं था लेकिन उसने यह स्पष्ट कर दिया कि अपीलकर्ता केंद्र से भाग गया था।

उपरोक्त साक्ष्य ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि जब अफीम उत्पाद की सुपुर्दगी के समय, जब इसे पीडब्ल्यू4 (लम्बरदार) बाबूलाल और अपीलकर्ता की उपस्थिति में तोला गया और जांचा गया, नमूना लेने और सील करने से पहले, अपीलकर्ता स्वेच्छा से मौके से भाग गया था।”

एनडीपीएस नियम, 1985 के नियम 18 में सरकारी अफीम कारखाने में भेजी गई अफीम से काश्तकार की उपस्थिति में नमूने लेने का प्रावधान है, यदि वह ऐसा चाहता है, तो उसे इस संबंध में तारीख और समय की सूचना देते हुए एक नोटिस काफी पहले भेजा जाएगा। एनडीपीएस नियम, 1985 का अध्याय III अफीम पोस्त की खेती और अफीम पोस्त के भूसे के उत्पादन का प्रावधान करता है। नियम 5 से नियम 30 विशेष रूप से अफीम और पोस्त के भूसे की खेती और उत्पादन का प्रावधान करते हैं, नियम 10 में प्रावधान है कि जिला अफीम अधिकारी प्रत्येक गांव में एक या अधिक अफीम पोस्त के काश्तकारों को लम्बरदार के रूप में नामित कर सकता है, जहां अफीम पोस्त को तराश कर रस निकालने के लिए अफीम की खेती के लिए लाइसेंस जारी किया गया है। नियम 12 में अफीम पोस्त के साथ खेती की गई भूमि के माप के संबंध में प्रक्रिया का प्रावधान है जबकि नियम 13 में प्रारंभिक तौल के संबंध में प्रक्रिया का प्रावधान है। नियम 14 उत्पादित अफीम की सुपुर्दगी का प्रावधान करता है और नियम 15 अफीम को तौलने और जांचने और वर्गीकृत करने का प्रावधान करता है, नियम 16 में प्रक्रिया का प्रावधान है जहां काश्तकार अफीम के वर्गीकरण से असंतुष्ट है। नियम 17 मिलावटी होने का संदेह होने पर अफीम भेजने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। नियम 18 नियम 16 या नियम 17 के तहत सरकारी अफीम कारखाने में भेजी गई अफीम से एक नमूना लेने का प्रावधान करता है। नियम 14 से नियम 18 को निम्नानुसार पुनरुत्पादित किया गया है:

“14. उत्पादित अफीम की सुपुर्दगी- अफीम पोस्त के साथ खेती की गई भूमि का सभी अफीम, काश्तकारों द्वारा जिला अफीम अधिकारी को या इस संबंध में नारकोटिक्स आयुक्त द्वारा विधिवत अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को ऐसे स्थान पर दिया जाएगा जैसा कि ऐसे अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

15. **अफीम को तौला, जांचा और वर्गीकृत किया जाना-** काश्तकारों द्वारा जिला अफीम अधिकारी या जैसा कि ऊपर अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को दी गई सभी अफीम को, संबंधित काश्तकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति और गांव के लम्बरदार की उपस्थिति में, उसकी गुणवत्ता और स्थिरता के अनुसार तौला, जांचा और वर्गीकृत किया जाएगा और जिला अफीम अधिकारी द्वारा सरकारी अफीम कारखाने को ऐसे तरीके से भेजा जाएगा जैसा कि नारकोटिक्स आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

16. **प्रक्रिया जहां काश्तकार अफीम के वर्गीकरण से असंतुष्ट है-** कोई भी काश्तकार जो नियम 15 में संदर्भित अधिकारी द्वारा किए गए अपनी अफीम के वर्गीकरण से असंतुष्ट हो सकता है, वह इसे अपनी उपस्थिति में और संबंधित लम्बरदार की उपस्थिति में ठीक से सील करने के बाद, ऐसे अधिकारी द्वारा सरकारी अफीम कारखाने को अलग से अग्रेषित करवा सकता है।

17. **मिलावटी होने का संदेह होने पर अफीम भेजने की प्रक्रिया-** जब जिला अफीम अधिकारी या इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को काश्तकार द्वारा दी गई अफीम में किसी विदेशी पदार्थ के साथ मिलावट होने का संदेह होता है, तो इसे काश्तकार और संबंधित लम्बरदार की उपस्थिति में ठीक से सील करने के बाद सरकारी अफीम कारखाने को अलग से अग्रेषित किया जाएगा।

18. **नियम 16 या नियम 17 के तहत सरकारी अफीम कारखाने में भेजी गई अफीम से नमूने लेना-** नियम 16 या नियम 17 के अनुसार अलग से प्राप्त सीलबंद अफीम को खोला जाएगा और काश्तकार की उपस्थिति में उसका नमूना लिया जाएगा, यदि वह ऐसा चाहता है, तो उसे इस संबंध में तारीख और समय की सूचना देते हुए एक नोटिस काफी पहले भेजा जाएगा।"

7. मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि नमूना लेने के लिए 05.04.2012 की तारीख तय की गई थी, जब अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता हजारी लाल जिला अफीम अधिकारी और लम्बरदार के सामने मौजूद था, क्योंकि उसके उत्पाद में मिलावट का संदेह था, हजारी लाल कंटेनर छोड़कर अचानक केंद्र से गायब हो गया। लम्बरदार की उपस्थिति में 50 ग्राम का नमूना लिया गया और अफीम को सील कर दिया गया। कुल 8.480 किलोग्राम अफीम बरामद की गई और इसमें मिलावट का संदेह था।

8. नियम 16 से 18 तक के उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से केवल नमूना लेने के लिए एक तारीख को अधिसूचित करने की आवश्यकता को इंगित करते हैं और जब कोई अनुपस्थित रहता है या अपनी अफीम को बिना देखभाल के मौके से भाग जाता है तो

इसका मतलब यह नहीं है कि नमूना नहीं लिया जा सकता है। नियम 16 से 18 का संयुक्त पठन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि नियम 18 के तहत नमूना लेना तब किया जाता है जब या तो काशतकार वर्गीकरण से असंतुष्ट हो या जहां अफीम में मिलावट का संदेह हो। यहाँ वर्तमान मामले में, वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा लाई गई अफीम में मिलावट का संदेह था और नमूना लेने के लिए 5 अप्रैल का दिन अधिसूचित किया गया था।

9. इस प्रकार, वर्तमान मामले में रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था जिसने इस तथ्य को स्थापित किया कि प्रावधान केवल एक तारीख को अधिसूचित करने के लिए था और इससे अधिक कुछ नहीं। यहाँ, नियम का पूरी तरह से पालन किया गया था और इसके अलावा प्रारंभिक बोझ को पूरा करने के बाद, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 और 54 के तहत एक अनुमान अभियुक्त के खिलाफ है, इसलिए उसे बोझ को पूरा करना होगा। यहाँ, ट्रायल कोर्ट का निर्णय स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अपीलकर्ता-अभियुक्त नमूना लेने के लिए तारीख की अधिसूचना के बारे में अच्छी तरह से जानता था। समन्वय पीठ ने उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है। इसके अलावा, जनादेश केवल अधिसूचना या सूचना के लिए था, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं।

9. यहाँ, यह अच्छी तरह से स्थापित किया गया था कि नमूना एक विशिष्ट अधिसूचित तारीख पर लिया गया था और उसके बाद नमूने का संग्रह जिला अफीम अधिकारी या इस संबंध में अधिकृत अन्य अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में था, भले ही काशतकार अनुपस्थित रहा हो। इसके अलावा, नियम 16 से 18 का उपयोग केवल अफीम में मिलावट के संदिग्ध मामलों में किया जाता है, इस प्रकार रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर ऐसे मामलों में अपीलकर्ता के सद्भाव को अनुमानित नहीं किया जा सकता है।

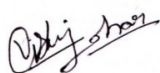
10. इसलिए, 27.01.2023 का आदेश वर्तमान मामले में लागू नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

11. इस प्रकार, दूसरी सजा के निलंबन की याचिका एतद्वारा खारिज की जाती है।

(अशोक कुमार जैन), जे

मोनू /9

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़